सरकारी व्यय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा किये जाने वाले व्यय को कहते है। वर्तमान समय में सभी देशों में सरकारी व्यय में वृद्धि हो रही है। सरकारी व्यय का अधिकाधिक सहारा इसलिए लिया जाता है ताकि इसके द्वारा देश के आर्थिक जीवन को प्रभावित किया जा सके। सार्वजनिक व्यय किसी भी देश के उत्पादन, आय के वितरण तथा रोजगार को प्रभावित करती है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार की मान्यता को स्वीकार कर लिया था इसलिए रोजगार में वृद्धि के लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत महसूस नहीं हुआ।

लेकिन 1930 की महामंदी ने पूंजीवादी देशों में व्यापक बेरोजगारी फैला दिया। आज में परिवर्तन से विनियोग पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज (r) में कमी करने से विनियोग (I) में वृद्धि होता है —

$$I = f(r) \quad ; \quad \frac{dI}{dr} < 0$$

महामंदी के समय ब्याज दर में बहुत कमी की गई किन्तु मौद्रिक नीति के द्वारा रोजगार एवं विनियोग में वृद्धि नहीं हो पाई।

J.M. Keynes का मत था कि मंदी काल में बेरोजगारी को समाप्त मौद्रिक नीति से दूर हो सकती है। ~~किन्तु~~ ब्याज दर को घटा कर Negative ब्याज दर (-r) कर देना चाहिए तभी पूर्ण रोजगार के स्तर पर बचत एवं विनियोग एक बराबर हो सकेगा। Don Patinkin ने Keynes

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

के इस विचार को निम्न चित्र द्वारा प्रस्तुत किया है—

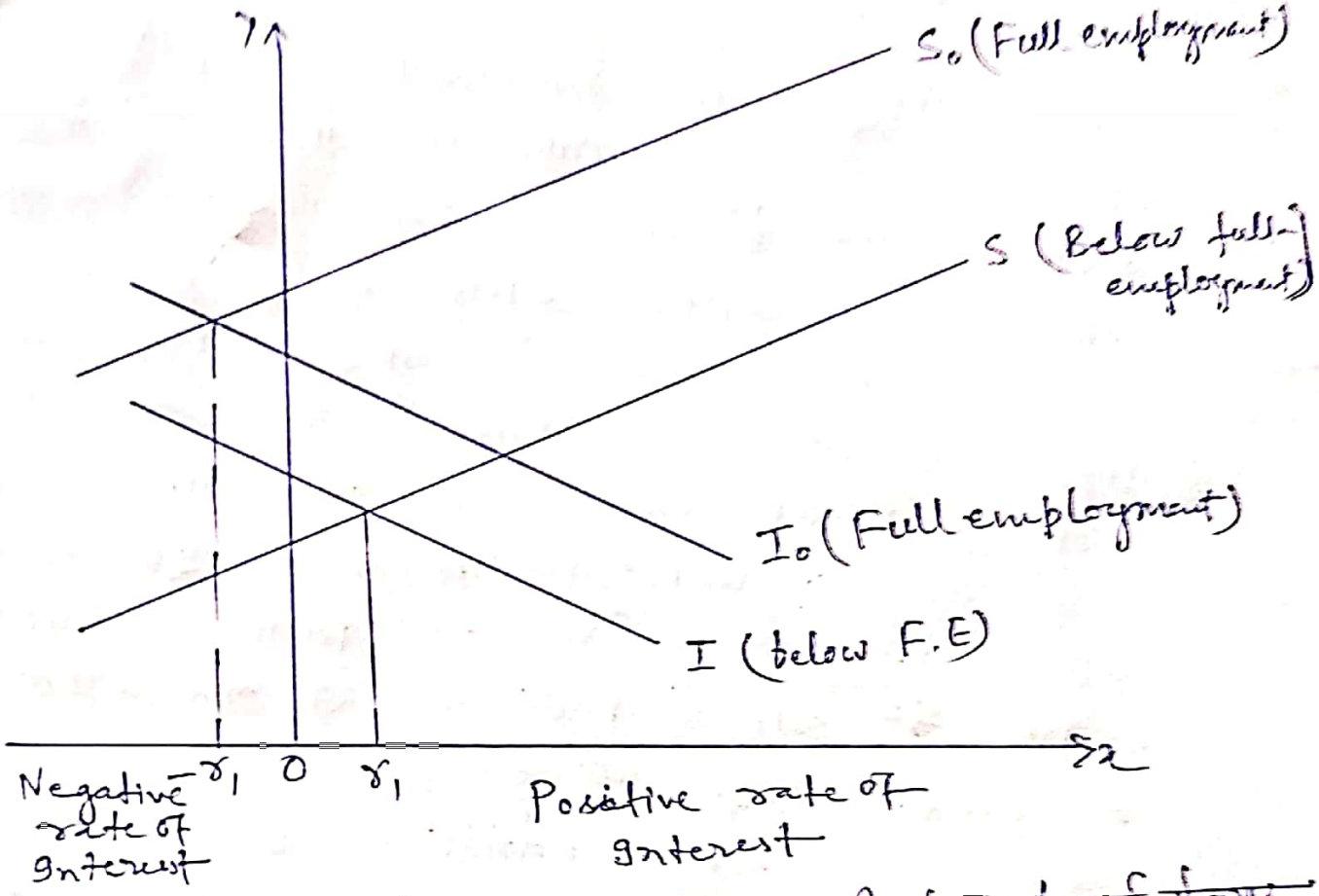

Keynes ने ब्याज परिवर्तन से पूर्ण रोजगार पाना मंदी काल में असंभव बतलाया है। चित्र से स्पष्ट है कि बचत विनियोग की तुलना में अधिक Interest elastic है।

Keynes ने पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत पर बल दिया। Laissez fair की समाप्ति तथा State Intervention की आवश्यकता को पूंजीवादी देशों में प्रचलित किया।

सार्वजनिक व्यय के द्वारा मंदी को दूर कर पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार वृद्धि के लिए सरकार को स्वयं विनियोग करना होगा। सरकारी व्यय निम्नलिखित तरीकों से करने पर पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो सकती है—

सार्वजनिक निर्माण कार्य

सरकार सार्वजनिक निर्माण की कुछ विशेष योजनाओं को चालू कर सकती है जैसे कि सड़कों, बांधों तथा पुलों आदि के निर्माण का कार्य। ऐसी योजनाओं से काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिल जाता है। जिससे उनकी क्रयशक्ति बढ़ जाती है। क्रयशक्ति बढ़ने से देश में वस्तुओं की कुल मांग में भी वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप अन्य उद्योगों में भी रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। सार्वजनिक निर्माण कार्य की योजनाओं पर किया जाने वाला खर्च मुफ्त सहायता देने के खर्च से श्रेष्ठ होता है क्योंकि एक तो इससे अनेक सार्वजनिक निर्माण कार्य संपन्न हो जाते हैं तथा दूसरे मुफ्त सहायता की योजनाओं से जो मानसिक गिरावट होती है उसकी की संभावना नहीं रहती है। सार्वजनिक व्यय उन योजनाओं पर किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक महत्व के हों।

पेंशन तथा लाभ

पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी को दूर कर पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए बेरोजगारी पेंशन अथवा लाभ को सार्वजनिक व्यय के द्वारा जनता को दिया जाना चाहिए। पेंशन एवं लाभ एक ऐसी निधि से दिये जाते हैं जो कि विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। इस निधि का निर्माण कर्मचारियों, मालिकों तथा सरकार के सम्मिलित अंशदान द्वारा होता है। अतः कर्मचारी इन निधियों से मिलने वाली अनुदानों को अपने अधिकार

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस संदर्भ में केवल एक आशंका बनी रहती है कि पेंशन का पूरा मुद्रा ~~व्यय~~ जनता द्वारा व्यय किया गया या नहीं।

व्यवसायहीन लोगों की सहायता

व्यवसायहीन लोगों की सहायता से मतलब यह है कि सरकार लोगों से कोई भी काम कराये बिना ही उन्हें सहायता अनुदान (Relief grant) देती है। ऐसे व्यय को स्थानान्तरण व्यय (Transfer Expenditure) भी कहा जाता है। क्योंकि यह धन वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के रूप में नहीं दिया जाता बल्कि धन का केवल स्थानान्तरण मात्र होता है। रोजगार के दृष्टिकोण से ऐसे खर्चों का लाभ यह है कि इनके द्वारा दिया हुआ लगभग सारा ही धन प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा पुनः खर्च कर दिया जाता है चूंकि ऐसी सहायता साधारणतः अत्यंत निर्धन व्यक्तियों को ही दी जाती है और चूंकि प्राप्तकर्त्ताओं को यह विश्वास रहता है कि जबतक वे बेरोजगार रहेंगे उन्हें ऐसी सहायता मिलती रहेगी, अतः सामान्यतः वे इसप्रकार प्राप्त सहायता का अधिकांश भाग अपनी उपभोग की आवश्यकताओं पर खर्च कर देते हैं। इस सबके बावजूद, ऐसे खर्चों में कुछ कमियाँ भी पाई जाती है। ऐसे खर्चे प्राप्त-~~कर्त्ता~~ कर्त्ताओं को प्रायः अरुचिकर लगते हैं क्योंकि इनमें दान या खैरात की गन्ध पाई जाती है। इससे प्राप्त-कर्त्ताओं का नैतिक स्तर भी गिर जाता है। इसलिए वृद्धों, अपाहिजों तथा विधवाओं।

को हटाकर अन्य लोगों को रोजगार का लाभ सार्वजनिक व्यय से नहीं पहुँचाया जाना चाहिए।

Keynes ने अपनी पुस्तक "The General theory of Employment, Interest and money" में बताया है कि रोजगार का निर्धारण effective demand के द्वारा होता है और effective demand का निर्धारण Aggregate demand function तथा Aggregate supply function के द्वारा होता है —

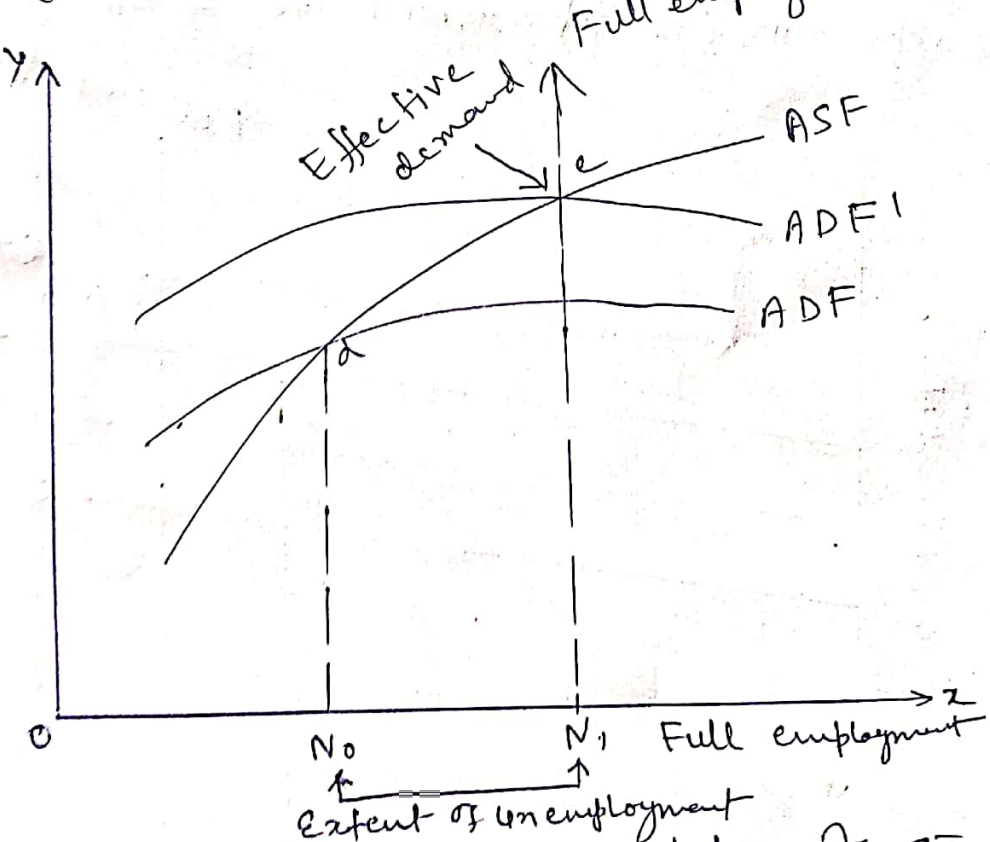

उपर के चित्र में स्पष्ट है कि बेरोजगारी का कारण effective demand में कमी है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ADF रेखा में upward shift लाकर पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त किया जा सकता है।

Keynes ने निवेश तथा रोजगार की व्याख्या करने के लिए Investment multiplier की धारणा को दिया जिसे आज हम Public

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

expenditure or Govt expenditure Multiplier के रूप में भी प्रदर्शित करते है —

$$K = \frac{1}{1 - \frac{\Delta C}{\Delta Y}} \quad \text{—————— (i)}$$

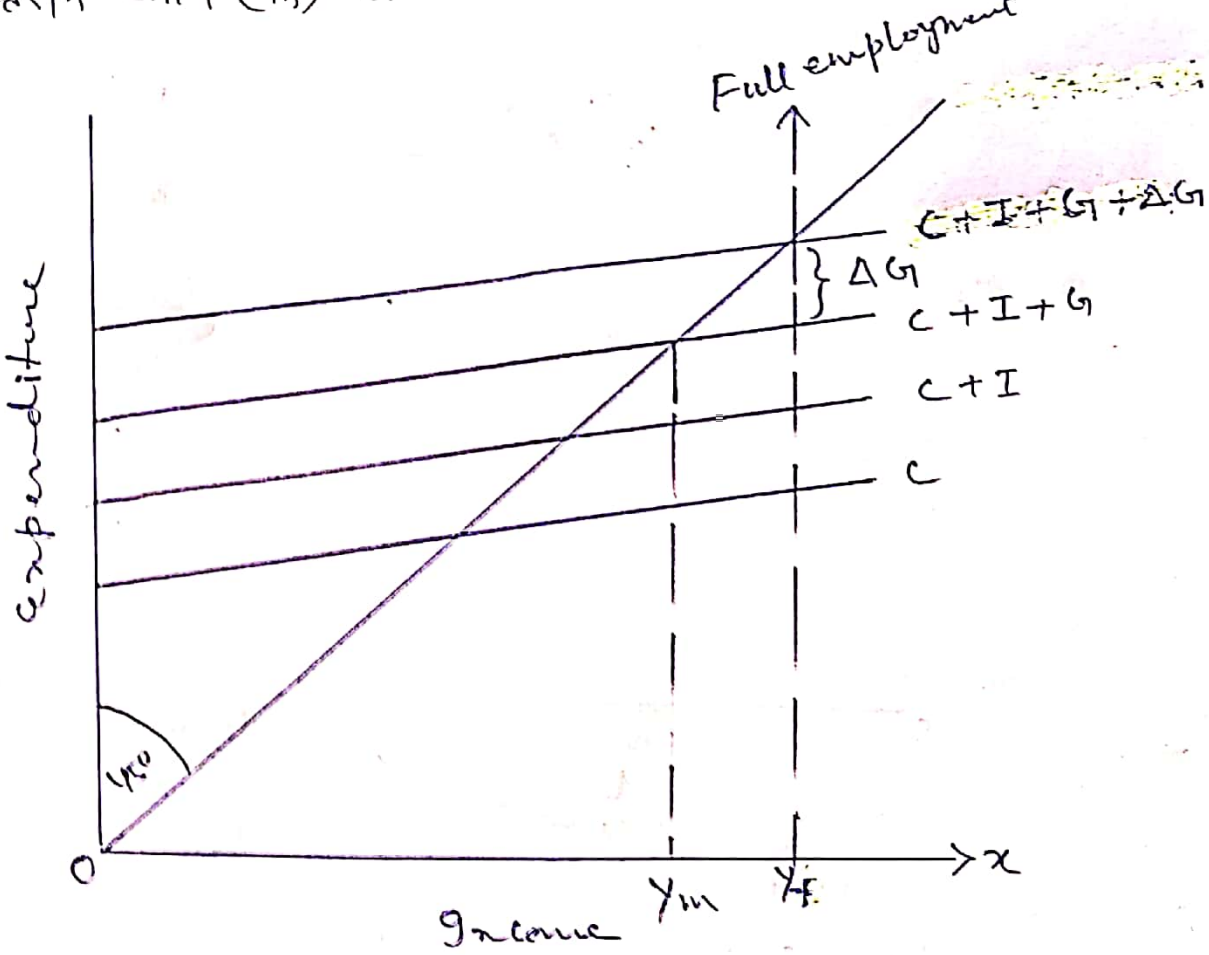

$$K_g = \frac{\Delta Y}{\Delta G} \quad \text{or} \quad \Delta Y = K_g \Delta G \quad \text{—— (ii)}$$

सार्वजनिक व्यय के द्वारा सरकार पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकती है। जिसे हम पूर्ण रोजगार स्तरीय आय (Y_f) से प्रदर्शित कर सकते है —

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि हम अगर ΔG के बराबर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करें तब आय का स्तर Below ~~fooll~~ full employment (Y_m) से पूर्ण रोजगार आय की स्तर (Y_f) प्राप्त कर सकती है।

Compensatory Public Expenditure

मंदी की अवधि में किया जानेवाला सरकारी व्यय को प्रतिकारी या क्षतिपूरक व्यय (Compensatory Expenditure) कहा जाता है। क्योंकि ये व्यय वस्तुओं के प्रति लोगों की व्यक्तिगत मांगों में उत्पन्न हुई कमी को पूरा करते हैं। Keynes के शब्दों में, सरकारी व्यय एक संतुलन तत्व है जो कि राष्ट्रीय आय को एक निश्चित स्तर पर कायम रख सकता है। व्यवसाय-चक्र के मंदीकाल में ऐसे खर्चों में आरोही क्रम से वृद्धि की जा सकती है। और जब आर्थिक क्रियाओं का स्तर फिर ऊपर उठने लगे तो ऐसे खर्चों में कमी भी की जा सकती है। 1930 के मंदी के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी तरह के खर्चे किये गये थे और उनसे काफी सफलता भी मिली थी। क्षतिपूरक व्यय सार्वजनिक निर्माण योजनाओं पर Infra-structural facilities के निर्माण पर किये जाते हैं।

Pump-Priming Public Expenditure

पूर्ण रोजगार की प्राप्ति तथा व्यवसायिक मंदी को स्थायी रूप से रोकने के लिए सरकार को Pump-priming public expenditure करना चाहिए। यदि काफी अधिक मात्रा में सरकारी खर्च किया जाए तो उनके द्वारा मंदी से उबरने का एक ऐसा क्रम चालू किया जा सकता है जो स्वयं प्रेरणा से ही एक अनिश्चित अवधि तक अपना कार्य जारी रख सके। ऐसे ही व्यय को Pump-priming

expenditure कहते है। जैसे किसी पम्प को चालू करने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है तो वह पम्प एक निरंतर जल की धारा के रूप में काफी समय तक पानी दे सकता है- इसी प्रकार यह सोचा गया कि मंदी के दिनों में सरकार एक बार कुछ धन खर्च कर दे तो आर्थिक जीवन का प्रवाह सदा के लिए सरलता के साथ जारी रखा जा सकता है।

इन सभी तरीकों से सरकारी व्यय के द्वारा पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है परन्तु इनमें सबसे अच्छा तरीका Compensatory public expenditure होती है जो पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

Dr Sandhya Rani